B.A. (Hons) Third Semester Examination, 2013

Political Science

Paper : Fifth (Indian Government and Politics, Part-1)

Paper code : AS-2635

Model Answer Key

Section – 'A'

खण्ड – 'अ'

Ques. No-1 :

(i) – (c) – French Revolution
फ्रांसीसी क्रान्ति

(ii) – (c) – Article 61
अनुच्छेद 61

(iii) – (d) – Article 51
अनुच्छेद 51

(iv) – 06 Months
06 महीने

(v) – (b) – Rajya Sabha
राज्य सभा

(vi) – (b) – Weimer Constitution of Germany
जर्मनी के वायमर संविधान से

(vii) – (c) – Lok Sabha, Rajya Sabha and President
राष्ट्रपति, लोक सभा और राज्य सभा

(viii) – (c) – Australia
आस्ट्रेलिया

(ix) – (d) – Attorney General
महान्यायवादी

(x) – (d) – Provided for An All India Federation
अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रवेश किया

Section – 'B'
खण्ड – 'ब'

Ques. No.2 **History of Constitutional Development in India:–**

The History of constitutional development in modern India can be fruitfully traced from 1773, when the British Parliament passed the Regulating Act and gave a broad coherence to the East India company's rule in India. – – –

(i) The Regulating Act, 1773.
(ii) – Pitts India Act, 1784
(iii) – Charter Act, 1853 The Act for the better governance in India, 1858
(iv) – Indian Councils Act, 1861, 1892
(v) – Morle-Minto Reforms, 1909
(vi) – Government of India Act, 1919
(vii) – The Government of India Act, 1935
(viii) – Indian Independance Act, 1947.

आधुनिक भारत के संवैधानिक विकास का उपवाहित ढंग से अध्ययन 1773 से किया जा सकता है क्योंकि इस वर्ष ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और भारत में कम्पनी के शासन को एक व्यापक स्वरूप देने का प्रयास किया – – –

(i) – रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
(ii) – पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
(iii) – चार्टर एक्ट, 1853, द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, 1858.
(iv) – इंडियन कांउसिल्स एक्ट्स 1861 एवं 1892
(v) – मार्ले - मिंटो सुधार, 1909
(vi) – भारत सरकार अधिनियम, 1919
(vii) – भारत सरकार अधिनियम, 1935
(viii) – भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947

Ques No. 3

Fundamental Duties (मौलिक कर्तव्य) (Part – IV A)

The following fundamental Duties of the citizen have been enumerated in Article 51 A of the Indian constitution –

(i)- To abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem.

(ii)- To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom.

(iii)- To upload and protect the sovereignty, unity and integrity of India.

(iv)- To defend the country and render National service when called upon to do so.

(v)- To promote Harmony and the spirit of common Brotherhood amongst all the people of India trancending Religious, Linguistic and Regional or sectional diversities, to renounce practices Derogatory to the dignity of women.

(vi)- To value and preserve the Rich Heritage of our composite culture.

(vii)- to protect and improve natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures.

(viii)- To develop a scientific temper, Humanism and the spirit of inquiry and Reform.

(ix)- To safeguard public Property and abjure violence.

(x)- To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.

(xi)- 86th constitutional Amendment – – – –

भारतीय संविधान के भाग-4A में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है:–

(i)- संविधान का पालन करने तथा इसके आदर्शों और संस्थाओ, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना।

(ii)- पवित्र आदर्शों जिन्होने हमारी स्वतन्त्रता के संघर्ष को उत्साहित किया, को स्मरण रखना और उन पर चलना।

(iii)- भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखण्डता को कायम रखना और रक्षा करना।

(iv)- आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित होना।

(v)- धार्मिक, भाषायी और क्षेत्रीय या जातीय विभिन्नताओं से ऊपर उठकर भारत के लोगों में साम्प्रदायिक सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को उत्साहित करना, महिलाओं के सम्मान को चोट पहुँचाने वाले व्यवहार को त्यागना।

(vi)- हमारी समुचित संस्कृति की अमीर विरासत का सम्मान करना और उसको संभालना।

(vii)- जंगलो, झीलो, नदियों और जंगली जीवन सहित प्राकृतिक वातावरण की संभाल और सुरक्षा तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना।

(viii)- वैज्ञानिक, मानववादी सोच और सुधार की भावना को विकसित करना।

(ix)- सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा और हिंसा त्यागना।

(x)- व्यक्तिगत और सामूहिक यत्नों के सभी क्षेत्रो में उन्नति के लिए संघर्ष करना ताकि देश निरन्तर प्रयासों और प्राप्तियों के उच्च स्तरों की ओर बढ़ता रहे।

(xi)- 86 वाँ संवैधानिक संशोधन – – – – –

Ques. No 4 The Preamble to the Indian Constitution -

— The Preamble to the Constitution, after the 42nd Amendment - - - -

Main features of the Preamble —

(I)- The Source of Authority - Popular Sovereignty.

(II)- Nature of State

A- India is a Sovereign State

B- India is a Socialist State

C- India is a Secular State

D- India is a Democratic State

E- India is a Republic

(III)- Objectives of the State: A- Justice

B- Liberty

C- Equality

D- Faternity

(IV)- Date of Adoption and Enactment to the Constitution

भारतीय संविधान की प्रस्तावना —

— 42 वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात संविधान की प्रस्तावना - - -

— प्रस्तावना की मुख्य विशेषताए —

(I)- सत्ता का स्रोत - लोकप्रिय प्रभुसत्ता

(II)- राज्य की प्रकृति — A- भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य है

B- भारत एक समाजवादी राज्य है

C- भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है

D- भारत एक लोकतन्त्रीय राज्य है

E- भारत एक गणराज्य है

(III)- राज्य के उद्देश्य — A - न्याय

B- स्वतन्त्रता

C- समानता

D- भ्रातृ - भाव

(IV)- संविधान को अपनाने और पारित करने की तिथि

Ques No-5 "The Prime Minister is the Key Stone of the Cabinet arch."

- Appointment of the Prime Minister — —
- No formal Qualification — —
- Tenure — — —

Powers and Functions of the Prime Minister

(I)- Formation of the Council Ministers —
(II)- Allocation of Portfolios - —
(III)- Reshuffling of Portfolios — —
(IV)- Chairman of the Cabinet — —
(V)- Removal of ministers
(VI)- Chief Link between the President and the Cabinet —
(VII)- Co-ordinator in Chief —
(VIII)- Leader of the Lok Sabha —
(IX)- Role of Economic Planning — —
(X)- Role as Leader of the Nation - —
(XI)- Role of Prime Minister during an Emergency — —.

"प्रधानमंत्री वह आधारशिला है जिस पर मंत्रिमंडल का मेहराब टिका होता है"

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति — — —
- कोई औपचारिक योग्यता नहीं — —
- कार्यकाल — —

प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य — —

(I)- मंत्रि-परिषद का गठन —
(II)- विभागों का बँटवारा —
(III)- विभागों में फेरबदल —
(IV)- कैबिनेट का चेयरमैन —
(V)- मंत्रियों को पदमुक्त करना — —
(VI)- राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच मुख्य सम्पर्क सूत्र — —
(VII)- प्रमुख तालमेलकर्ता —
(VIII)- सदन का नेता — —
(IX)- आर्थिक नियोजन में भूमिका — —
(X)- संकटकाल की स्थिति के दौरान प्रधानमंत्री की भूमिका —

Ques No-6 - Rajya Sabha — The Council of States

- The Rajya Sabha is the Upper House of the Union Parliament.
- Composition of the Rajya Sabha - -
Powers and functions of the Rajya Sabha - —

(I) Legislative Powers —
(II) Financial Powers —
(III) Executive Powers —
(IV) Amendment Powers —
(V) Electoral Powers —
(VI) Judicial Powers —
(VII) Miscellaneous Powers —
(VIII) Special Powers of Rajya Sabha — — — Article 312
Article 249

राज्य सभा - राज्यों की परिषद

राज्य सभा अर्थात राज्यों की परिषद संघीय संसद का उच्च सदन है - -

- राज्य सभा की रचना - -
- राज्य सभा की शक्तियां और कार्य - -

(I) - वैधानिक शक्तियाँ - -
(II) - वित्तीय शक्तियाँ - -
(III) - कार्यपालिका शक्तियाँ - -
(IV) - संशोधन की शक्तियाँ - -
(V) - चुनाव से संबंधित शक्तियाँ - -
(VI) - न्यायिक शक्तियाँ —
(VII) - कुछ अन्य शक्तियाँ —
(VIII) - राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ —
- अनुच्छेद 312
- अनुच्छेद 249

Ques No-7 – Judicial Review : Meaning and Definition

– Judicial Review in India – –

Constitutional Basis of Judicial Review in India – –

(I) – Article 13
(II) – Article 32
(III) – Article 131 and 132
(IV) – Article 226
(V) – Article 246
(VI) – Article 124(6) and Article 219

Other features of the Constitution also provide for the Judicial Review power of the Court – –

(1) – The Principle of Limited Government – –
(2) – Federalism – –
(3) – written Rights – –
(4) – The Exercise of Judicial Review Power by the Judiciary – –
(5) – 42nd and 43rd Amendments – –

न्यायिक पुनर्निरीक्षण : अर्थ और परिभाषा – –

– भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण – –

– भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण के संवैधानिक आधार –

(I) – अनुच्छेद 13
(II) – अनुच्छेद 32
(III) – अनुच्छेद 131 एवं 132
(IV) – अनुच्छेद 226
(V) – अनुच्छेद 246
(VI) – अनुच्छेद 124(6) और अनुच्छेद 219

संविधान की अन्य विशेषताएँ जो न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है –

(1) – सीमित सरकार का सिद्धान्त –
(2) – संघवाद –
(3) – लिखित अधिकार –
(4) – न्यायपालिका की ओर से न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति का प्रयोग –
(5) – 42वाँ और 43वाँ संशोधन –

Ques. No- 8 - What is Funamental Rights? - Part - III

- Right to Constitutional Remedies (Article 32)

The Right to move the court for securing the fundamental rights is enshrined in the Constitution. Article 32 Provides effective provisions for the protection and enforcement of the fundamental rights ---

The writs - -

- The writ of Habeas Corpus - -
- writ of Mandamus - - -
- writ of Prohibition - - -
- writ of Quo - Warranto - -
- writ of Certiorari - - -

मौलिक आधिकार क्या है? - भाग तीन

- संवैधानिक उपचारों का अधिकार - - (अनुच्छेद 32)

संविधान में मौलिक आधिकारों की सुरक्षा करने के लिए नागरिकों को न्यायालय की सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है. अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लागू करने की प्रभावशाली व्यवस्था प्रदान करता है - -

निम्न हुक्मनामें जारी किये जा सकते है - -.

- व्यक्ति को पेश किये जाने का आदेश - -
- फ़ुरमान आदेश - -
- मनाही -
- अधिकार परीक्षा आदेश -
- उत्प्रेषण आदेश -